उत्तर प्रदेश में बना एक नया जिला

यह जिला अभी तक प्रयागराज क्षेत्र में आता था, इस जिले का नाम है महाकुंभ मेला, हालांकि यह जिला अस्थायी जिला है

यूपी में अब 75 नहीं 76 जिले! योगी सरकार ने इस पवित्र क्षेत्र को घोषित किया नया जिला

● मंथन संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब तक आप पढ़ते आ रहे थे कि प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, अगर अब आप अपडेट नहीं हुए तो गलत हो जाएंगे क्योंकि योगी सरकार ने प्रदेश में एक नया जिला बना दिया है। यह जिला अब तक प्रयागराज जिले में आता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एक नया जिला घोषित कर सभी को चौंका दिया है। यह जिला अभी तक प्रयागराज क्षेत्र में आता था, लेकिन अब इसे प्रयागराज से अलग कर एक नया नाम दे दिया गया है। इस जिले का नाम है महाकुंभ मेला। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक मीटिंग कर अधिकारियों को आदेश दिए। जिसके बाद प्रयागराज के जिलाधिकारी ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर लोगों को सूचना दी। हालांकि यह जिला अस्थायी जिला है।

बीते दिन लिया गया फैसला: यह फैसला बीते दिन एक दिसम्बर को लिया गया है। प्रयागराज डीएम ने इस निर्णय के तहत नए

महाकुंभ मेला जिले का गठन किया है। जानकारी दे दें कि यह फैसला आगामी कुंभ मेले के प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए लिया गया, ताकि जनवरी 2025 में होने वाले भव्य धार्मिक आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। डीएम के जारी आदेश के मुताबिक, नवगठित जिला महाकुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा। कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से मैनेज करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

आदेश किया गया जारी: सरकारी आदेश में कहा गया, 'मैं, रविन्द्र कुमार मांदड़, जिला मजिस्ट्रेट, शासन के पत्र संख्या-3966/9-1-2024-408057 दिनांक 25.11.2024 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज अधिनियम, 2017 की धारा 2(ध) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाकुंभ 2025 के आयोजन हेतु महाकुंभ मेला जिला घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी करता हूं। महाकुंभ मेला जिले की सीमा निम्नानुसार होगी। अनुलग्नक-ङ में वर्णित राजस्व गांवों और संपूर्ण परेड क्षेत्र का क्षेत्रफल महाकुंभ मेला जिला/मेला क्षेत्र में शामिल होगा।'

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश: आदेश में आगे कहा गया है कि, 'महाकुंभ मेला जनपद/मेला क्षेत्र में मेलाधिकारी, कुंभ मेला, प्रयागराज को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14(1) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी तथा उक्त संहिता या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी तथा उक्त जनपद में अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 4, 2016)) की धारा-12 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन सभी श्रेणी के मामलों में कलेक्टर की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कलेक्टर के समस्त कार्यों का संपादन करने का अधिकार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।' गौरतलब है कि हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला आगामी महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा।

युद्ध और तनाव के हालातों के बीच खूब बढ़ी हथियारों की डिमांड

जंग से चमकी हथियार कंपनियों की किस्मत, साल भर में बिक गए 632 अरब डॉलर के आम्स

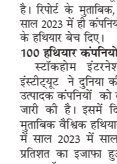

● मंथन विदेश ब्यूरो

स्टॉकहोम। बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वो इसी ओर इशारा करते हैं कि युद्ध और तनाव के चलते हथियारों की ताबड़तोड़ बिक्री हुई है, जिससे इन्हें बनाने वाली कंपनियों के रेवेन्यू में तगड़ा उछाल आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन संघर्षों के बीच साल 2023 में हीं कंपनियों ने 632 अरब डॉलर के हथियार बेच दिए।

100 हथियार कंपनियों का डाटा जुटाया

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया की टॉप-100 हथियार उत्पादक कंपनियों को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें दिए गए आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक हथियार कंपनियों के रेवेन्यू में साल 2023 में सालाना आधार पर 4.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और ये 632 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। खासतौर पर यह बढ़ोतरी रूस-यूक्रेन में युद्ध समेत अन्य संघर्षों और इंडो-पैसिफिक सेक्टर में बढ़ते तनाव के बीच हथियारों की जोरदार बिक्री को दर्शाती है।

हथियारों के उत्पादन में टॉप पर अमेरिका

हथियारों के प्रोडक्शन के मामले में अमेरिका ने ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा हुआ है और टॉप-100 में से यहां की 41 कंपनियों ने 317 अरब डॉलर का योगदान दिया है, जो कि हथियार कंपनियों के कुल वैश्विक रेवेन्यू का 50 प्रतिशत के आस-पास है। साल 2022 की तुलना में इसमें 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

दूसरे नंबर पर चीन का दबदबा: वैश्विक हथियार राजस्व में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता चीन रहा है। देश में टॉप-100 में 9 कंपनियों ने इसमें 103 अरब डॉलर का रेवेन्यू जोड़ा है। हालांकि, चीन में हथियार प्रोडक्शन और बिक्री की ये चाल सालाना आधार पर 0.7 प्रतिशत घटी है और ये 2019 के बाद से सबसे कम है।

भारत का हथियार राजस्व भी बढ़ा

बात करें भारत की, तो रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया का आर्म्स रेवेन्यू 2023 में 6.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 5.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

बीजेपी का चुनावी वादा

बीजेपी नेता बिधूड़ी ने घोषणा की कि अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो सभी योजनाएं पूर्ववत जारी ही रहेंगी

'दिल्ली फतह' के लिए 'आप' का ही चुनावी हथियार अपनाएगी बीजेपी? बनाया ये बड़ा महाप्लान

● मंथन संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने में बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है और सभी सियासी दल दिल्ली फतह की तैयारी में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में अपना वनवास खत्म करने की बेकरार है। वह केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए इस बार उनका ही तरीका अपनाने की तैयारी कर रही है। इस बार वह फ्री की स्कीम पर दांव लगाने जा रही है।

भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर वह सत्ता में आई तो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली, पानी और बस में सफर की सुविधा जारी रहेगी। बीजेपी ने यह वादा उस वक्त किया है जब केजरीवाल अपने प्रचार अभियान में कह रहे हैं कि अगर बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आई तो वह फ्री की सभी स्कीमों को बंद कर देगी।

जारी रहेंगी सभी योजनाएं- रामवीर सिंह बिधूड़ी

बीजेपी नेता और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आती है तो फ्री बिजली, पानी और महिलाओं के लिए सफर जैसी योजनाएं जारी ही रहेंगी। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि पार्टी गुरुवार से पार्टी दिल्लीवालों से घोषणा पत्र को लेकर सुझाव लेगी।

बीजेपी की पहली लिस्ट में हो सकते हैं कई बड़े नेता

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता यह प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो फ्री की स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। वह केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी ना केवल इन स्कीम्स को जारी रखेगी बल्कि इनकी खामियों को भी दूर करेगी।

आप ने बताया जुमला: बीजेपी के वादे पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है और इसको सिर्फ जुमला बताया है। आप की प्रवक्ता प्रियंका ककड्ड ने कहा कि दिल्ली के लोग बीजेपी के जुमले में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमे पता है बीजेपी शासित राज्यों में 8 घंटे के पॉवर कट लगते हैं। हमे पता है की गलती से भी अगर बीजेपी दिल्ली में आ गई तो सारे डिस्कॉम अडानी को बेच देगी और महंगी बिजली से जनता की कमर तोड़ने का काम करेगी। केजरीवाल के खिलाफ दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटों समेत इन दिग्गजों पर लगा सकती है दांव बीजेपी।

तंगी के बाद भी बोस्टन जाकर की पढ़ाई, आज यूके के सबसे बड़े बिजनेसमैन

स्वराज पॉल का जन्म 18 फरवरी 1931 में पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था। उनके पिता एक छोटा ढलाईखाना चलाते थे जहाँ बाल्टियाँ और कृषि उपकरणों का निर्माण होता था। टांडा रोड पर पिता और चाचा-ताऊ के एक जैसे बिजनेस। कॉपीटिटर भी। मगर परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ। 1944 में चाचा खेमचंद नहीं रहे। पिता गश खा बैठे। तब तो ठीक हो गए। मगर तीन महीने के अंदर एक दिन बरांडे में गिरे और चले गए। भाई के गुजरने पर उन्होंने कहा था – मैं तेरा खाता लेकर आता हूं। तब कोई यह गूढ़ बात समझ नहीं पाया। तभी बंटवारा हुआ। मारकाट मची। स्वराज उस आखिरी ट्रेन में थे, जो सहीसलामत यहां आई।

उनकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर के फॉरमैन क्रिस्चियन कॉलेज से हुई जिसके बाद उन्होंने जालंधर के दोआबा कॉलेज से भी शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात उन्होंने बी.एस.सी, एम.एस.सी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अमेरिका के मशहूर मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईटी) से की। एमआईटी से निकलने बाद उन्होंने भारत में अपने पारिवारिक कंपनी 'एपीजे-सुरेन्द्र ग्रुप'

में कार्य किया। इस कंपनी की स्थापना उनके पिता ने की थी और उस समय इसका संचालन स्वराज पॉल के दो बड़े भाई - सत्य पॉल और जीत पॉल - कर रहे थे।

लार्ड स्वराज पॉल कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदों पर रह चुके हैं। वे थेम्स वैली विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर (1998) और उसके गवर्नर (1992-97) के पद पर आसीन रहे। सन 1998 से वे यूनिवर्सिटी ऑफ़ वॉलवेर्हम्प्टन और यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेस्टमिंस्टर के चांसलर रहे जिसमें उनके पारिवारिक ट्रस्ट ने लगभग 300,000 का योगदान दिया। उन्होंने 'अम्बिका पॉल फाउंडेशन' के माध्यम से 'यूनिवर्सिटी ऑफ़ वॉलवेर्हम्प्टन' को उदारतापूर्वक दान दिया और इसके 'स्टूडेंट्स यूनियन सेण्टर' का नवीनीकरण का खर्चा भी वहन किया। नवीनीकरण के बाद उसका नाम 'द अम्बिका पॉल स्टूडेंट्स यूनियन सेंटर' कर दिया गया।

पुरस्कार और सम्मान: लार्ड स्वराज पॉल को कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं जिनमें यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, भारत, रूस और स्विट्ज़रलैंड के विश्वविद्यालयों द्वारा मानद सम्मान भी शामिल हैं।

सन 1983 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया

इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर ने उन्हें 'भारत गौरव' सम्मान दिया।

विवाद: लार्ड स्वराज पॉल का नाम ब्रिटेन के 'सांसद व्यय घोटाले' में आया था। इसके अंतर्गत सांसदों ने गलत ढंग से भत्ते का दावा किया था। सांसद व्यय घोटाले की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन और कंजरवेटिव नेता डेविड कैमरॉन समेत कई अन्य सांसदों को दावे की राशि का भुगतान करना पड़ा था।

'यह हिंसा मैच रेफरी द्वारा एक विवादित निर्णय के साथ शुरू हुआ, इसके बाद फैंस ने पिच पर हमला कर दिया'

गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान भिड़े फैंस, 100 से ज्यादा के मरने की आशंका, पुलिस स्टेशन भी जलाया

● मंथन विदेश ब्यूरो

कोनाक्री (गिनी)। सोशल मीडिया पर इस हिंसा के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इस वीडियो में मैच के बाहर सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल दिख रहा है और कई शव जमीन पर पड़े हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एन 'जेरेकोर पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी: एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, 'यह हिंसा मैच रेफरी द्वारा एक विवादित निर्णय के साथ शुरू हुआ। इसके बाद फैंस ने पिच पर हमला कर दिया।' स्थानीय मीडिया ने कहा कि यह मैच गिनी के जुंटा नेता ममादी डौंबौया के सम्मान में आयोजित एक टूर्नामेंट का हिस्सा था। डौंबौया 2021 के तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया था और खुद को राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया था।

डौंबौया ने राष्ट्रपति को बलपूर्वक हटाया था

डौंबौया ने सितंबर 2021 में राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को उखाड़ फेंककर बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा कर लिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि अल्फा ने ही डौंबौया को कर्नल के पद पर रखा था ताकि वह इस तरह के तख्तापलट से राज्य और उनकी रक्षा करने का काम करें। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव में डौंबौया ने 2024 के अंत तक एक नागरिक सरकार को सत्ता वापस सौंपने का वादा किया था।